RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 31 AUGUST 2022 TO 06 SEPTEMBER 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 51 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सीमाशुल्क विभाग आयातित वस्तुओं के लिए पांच सितंबर से एक समान जांच प्रणाली शुरू करेगा Page 3

सरकार 'भारत' ब्रांड के तहत बेचेगी सभी सब्सिडी वाले उर्वरक Page 5

एमजी मोटर इंडिया ने पेश की एडवांस ग्लॉस्टर Page 7

editoria!

रक्षा में आत्मनिर्भरता

भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले 780 वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है. दिसंबर, 2023 से दिसंबर, 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जायेगा. ये चीजें भारत में ही निर्मित की जायेंगी. उल्लेखनीय है कि यह तीसरी ऐसी सूची है. पिछले वर्ष दिसंबर और इस वर्ष मार्च में दो सूचियां जारी हुई थीं. आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के इस प्रयास के तहत 2500 चीजों का देश में उत्पादन हो रहा है तथा उनके आयात की अब कोई आवश्यकता नहीं है. सूचियों में शामिल आयातित हो रहीं 458 वस्तुओं में से भी 167 का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है. इस पहल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की आयात पर निर्भरता घटेगी तथा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. उल्लेखनीय है कि महामारी के दौर में दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया था. रक्षा क्षेत्र में यह प्रयास पहले ही प्रारंभ हो गया था. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी थी कि बीते चार-पांच वर्षों में रक्षा आयात लगभग 21 प्रतिशत कम हुआ है. आत्मनिर्भरता के लिए आयात घटाने के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा साजो-सामान दूसरे देशों को बेचे गये थे. घरेलू रक्षा उद्योग में बढ़ोतरी का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उक्त निर्यात का 70 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र के उद्योगों ने उत्पादित किया था. केंद्र सरकार ने 2020 में पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 35 हजार करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. अनुमान है कि 2025 तक भारतीय रक्षा उद्योग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा. बढ़ती रक्षा आवश्यकताओं के कारण आठ वर्षों में बजट आवंटन भी बढ़ता रहा है. आम तौर पर इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा आयात पर खर्च होता रहा है. पर अब विदेशी मुद्रा की बचत भी हो रही है तथा घरेलू उद्योगों का विकास भी हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के लिए 75 स्वदेशी तकनीकों और उत्पादों के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत भी की है. अभी देश में 30 युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है. इस वर्ष के रक्षा बजट में घरेलू हथियारों की खरीद को बढ़ावा देने हेतु 68 प्रतिशत और शोध एवं विकास कार्यों हेतु निजी क्षेत्रों, नवउद्यमों तथा अकादमिक क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत पूंजी परिव्यय का प्रावधान किया गया है. आयात कम होने और निर्यात अधिक होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी सामरिक स्थिति में मजबूती आयेगी.

कच्चा तेल 104 डॉलर प्रति बैरल पार, पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी जारी है। ओपेक एवं सहयोगी देशों के उत्पादन में कटौती की आशंका से क्रूड ऑयल के दाम में 3 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा की तेजी आई है। फिलहाल ब्रेंड क्रूड 104.20 डॉलर प्रति बैरल पर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 96.56 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 94.27 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि ओपेक एवं सहयोगी देशों के उत्पादन में कटौती की आशंका से कच्चे तेल के दाम में 3 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज ब्रेंट क्रूड 104.20 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 96.61 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। दरअसल हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी जारी है। इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल का दाम घरेलू बाजार में पिछले 7 अप्रैल, 2022 से स्थिर बना हुआ है

कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट

उत्पादन में कमी ला सकता है सऊदी अरब

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 महीने से दुनिया में बढ़ती महंगाई और OPEC+ कंट्री के तेल सप्लाई को कट करने की संभावना के कारण कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 महीने से दुनिया में बढ़ती महंगाई और OPEC+ कंट्री के तेल सप्लाई को कट करने की संभावना के कारण कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार को 0.3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 104.70 डॉलर प्रति बैरल रहा। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल के कीमत में सोमवार को 4.1 पर्सेंट का इजाफा देखने मिला था। ळए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत भी सोमवार को 0.2 पर्सेंट की गिरावट के साथ 96.79 डॉलर प्रति बैरल रहा।

बढ़ती महंगाई की वजह से बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम

दुनिया के बहुत सारे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में महंगाई double-digit तक पहुंच गया है। पिछले 50 सालों में कच्चे तेल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा गया है। दूसरी ओर अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित यूरोप के कई केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेशकों में चिंता का माहौल है। अंतरराष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस के तेल उत्पादन में काफी इजाफा हो गया। हालांकि पश्चिमी देशों की प्रतिबंधों के कारण लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि IEA के सदस्य देश जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व (SPR) से तेलों की सप्लाई कर सकते हैं।

तेल उत्पादन में कमी ला सकता है सऊदी अरब

हाल ही में ईरान ने ऑयल मार्केट में वापस आने की बात कही है। अब ईरान चाहता है कि वह वर्ल्ड पावर के साथ अपना न्यूक्लियर डील सिक्योर कर ले। ईरान के इस कदम के बाद से ही सऊदी अरब ने OPEC देशों को तेल के उत्पादन में कमी लाने को कहा है। पिछले सप्ताह ही OPEC देशों के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने के संकेत दिए थे। OPEC+ जिसमें OPEC कंट्री के अलावा रूस और अन्य कच्चे तेल के उत्पादक देश पॉलिसी निर्धारण के लिए 5 सितंबर को बैठक करेंगे।

यूक्रेन युद्ध, महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारत ने कई मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया: बिड़ला

नयी दिल्ली। एजेंसी

रूस-यूक्रेन युद्ध और महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने शुक्रवार को यह बात कही। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के शेयरधारकों को संबोधित करते हुए बिड़ला ने कहा कि वर्ष 20202 महामारी से अभूतपूर्व रूप से प्रभावित हुआ। इसके बाद 2021 में आपूर्ति पक्ष का संकट और फिर 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की चुनौतियों का सामना हुआ। बिड़ला ने कहा कि वैश्विक गतिरोध 2022 को अभूतपूर्व बना रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि व्यवधान अब स्थाई हो गया है। उन्होंने कहा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था इन वैश्विक घटनाक्रमों से अछूती नहीं रही है। भारत में मुद्रास्फीति का दबाव, आरबीआई द्वारा दरों में बढ़ोतरी और व्यापार घाटा भी देखा गया है। हम मुद्रा बाजारों में भी काफी अशांति देख रहे हैं।'' बिड़ला ने कहा कि इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें एक मजबूत पुनरुद्धार चक्र और चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर का अनुमान शामिल है।

News यू केन USE

पेट्रोरसायन क्षमता का विस्तार करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी रिलायंस

मुंबई। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी पेट्रोरसायन क्षमता का विस्तार करने के लिए अगले पांच साल में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निवेश पीटीए संयंत्र स्थापित करने, पॉलिएस्टर क्षमता का विस्तार करने, विनाइल श्रृंखला की क्षमता को तीन गुना करने और संयुक्त अरब अमीरात में एक रासायनिक इकाई स्थापित करने में किया जाएगा।

10 देशों की 24 कंपनियों ने श्रीलंका में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने में दिलचस्पी दिखाई: रिपोर्ट

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका के बिजली और ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत सहित 10 देशों की 24 कंपनियों ने संकटग्रस्त देश में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने में रुचि दिखाई है। समाचार पोर्टल कोलंबो पेज ने यह जानकारी दी। श्रीलंका इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और वहां विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका की बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन, मलेशिया, नॉर्वे और फिलीपींस की 24 कंपनियों ने अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा किए हैं। इन कंपनियों ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति अब इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी, और छह सप्ताह में प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी।

भारत दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में से एक: हार्वर्ड प्रोफेसर पोर्टर

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में से एक है और इसके पास अत्यधिक ताकत और क्षमता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (एचबीएस) के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर ने मंगलवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े पोर्टर ने कहा कि भारतीय सफल होना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत द्वारा 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को एकीकृत करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में एचबीएस के प्रोफेसर क्रिश्चियन केटेल्स ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है, जिनके पास अपने सभी नागरिकों के लिए वृद्धि के अवसरों को बढ़ाने की सबसे अधिक क्षमता है।

रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के लिए प्रतिक्रिया लेने को अगले दौर का सर्वे शुरू किया

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति को लेकर उम्मीदों और उपभोक्ताओं के भरोसे का आकलन करने के लिए मंगलवार को परिवारों का अगले दौर का सर्वे शुरू किया। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस सर्वे के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी सूचना प्रदान कराते हैं। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के सितंबर 2022 (आईईएसएच) दौर में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोज़गार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। यह सर्वे नियमित रूप से 19 शहरों में कराया जाता है। यह सर्वे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में कराया जाएगा। रिजर्व बैंक की अगली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 28-30 सितंबर को होगी।

पेट्रोलियम कंपनियों को अब पेट्रोल-एलपीजी पर घाटा नहीं, डीजल पर नुकसान बरकरार

नयी दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने से भारतीय ईंधन वितरक कंपनियां पेट्रोल और रसोई गैस में अपनी लागत की भरपाई करने की स्थिति में पहुंच गई हैं लेकिन डीजल की बिक्री पर उन्हें अब भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच महीनों में कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में लगातार होने वाली उठापटक की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किए। उन्होंने कहा, "एक दिन में पांच-सात डॉलर प्रति बैरल तक दाम घट-बढ़ रहे थे। इस तरह के उतार-चढ़ाव की स्थिति में हम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाल सकते थे। कोई भी वितरक इस तरह के उतार-चढ़ाव का बोझ नहीं डाल सकता है।"

बीपीसीएल के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ने भी करीब पांच महीने तक पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। बीपीसीएल के मुखिया ने कहा, "इस तरह के हालात में हमने खुद ही कुछ नुकसान सहने का फैसला किया। उस समय हमें यह उम्मीद भी थी कि हम आगे चलकर इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे।"

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम ज्यादा होने पर एक समय पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर 20-25 रुपये और पेट्रोल पर 14-18 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में गिरावट आने के बाद यह नुकसान भी अब काफी कम हो गया है। सिंह ने कहा, "अगले महीने से एलपीजी पर किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा। इसी तरह हमें पेट्रोल पर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन डीजल पर अब भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है।" उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ऐसी स्थिति नहीं बनी रह सकती है। उन्होंने कहा, "अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी या सरकार से अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ति की हमें जरूरत होगी।" हालांकि, उन्होंने यह ब्योरा नहीं दिया कि सार्वजनिक पेट्रोलियम वितरक कंपनियों को इस समय कितना घाटा उठाना पड़ रहा है।

प्रयोगशाला में तैयार हीरे की वृद्धि संभावनाओं पर गोयल ने की बैठक

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को प्रयोगशालाओं में तैयार हीरे के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर इस क्षेत्र की मजबूती के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की। गोयल ने बैठक के बाद अपने एक ट्वीट में कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय हीरा उद्योग को आगे ले जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, "प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले हीरे पर ध्यान देकर दुनिया के हीरा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की छवि को मजबूत किया जा सकेगा।"

प्रयोगशालाओं में कृत्रिम हीरे का निर्माण आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से किया जाता है। हालांकि, यह हीरा भी रासायनिक एवं भौतिक रूप में और देखने में एकदम प्राकृतिक हीरे के समान होता है। फिलहाल भारत प्रयोगशाला में तैयार हीरे के वैश्विक उत्पादन में करीब 15 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत में इस हीरे का प्रसंस्करण केमिकल वेपोर डिपॉजिशन के जरिये किया जाता है। प्रयोगशालाओं में तैयार हीरों का इस्तेमाल आभूषण उद्योग के अलावा कंप्यूटर चिप्स, उपग्रह और 5जी नेटवर्क में भी किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है: देबरॉय

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, बशर्ते कि अगले 25 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 7-7.5 प्रतिशत हो। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने मंगलवार को यह अनुमान जताया। देबरॉय ने 'भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का मसौदा 100' जारी करते हुए कहा कि अगर देश अगले 25 वर्षों में 7-7.5 प्रतिशत की औसत आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ता है, तो देश की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 10,000 अमेरिकी डॉलर अधिक होगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत भी उच्च मानव विकास श्रेणी के देशों में शामिल हो जाएगा। इस समय भारत 2700 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश को वर्तमान में एक विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

फिर 100 डॉलर से नीचे आया कच्चा तेल, जानिए क्या है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का भाव

नयी दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमत में मंगलवार को गिरावट आई। महंगाई से पूरी दुनिया परेशान है। इससे आने वाले दिनों में तेल की मांग प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही इराक में संघर्ष के बावजूद वहां से कच्चे तेल की निर्यात प्रभावित नहीं हुआ है। इन कारणों के मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल कीमत में प्रति बैरल करीब तीन डॉलर की गिरावट आई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में यह 100 डॉलर से नीचे आ गया। हालांकि, भारतीय बाजार में आज यानी बुधवार को भी भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ।

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। मायानगरी मुंबई में

पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में शुक्रवार को पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

कब बदली थी पेट्रोल की कीमत

यूं तो इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी ही हैं। लेकिन बीते सात अप्रैल से इसके दाम में कोई घट-बढ़ नहीं हुई है। 22 मई से सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का फैसला किया। इससे दिल्ली में पेट्रोल का दाम घट कर 96.72 रुपये पर आ गया। पिछले साल सितंबर के बाद पेट्रोल के मुकाबले डीजल का बाजार ज्यादा तेज हुआ था। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन भारत के खुले बाजारमें पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है। इस साल 22 मार्च से डीजल की कीमतें पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं। हालांकि बीते 7 अप्रैल से इसके दाम भी स्थिर हैं। 22 मई को दिल्ली में इसकी कीमतों में 7.35 पैसे कमी हुई थी। उसके बाद इसके दाम घट कर 89.62 रुपये प्रति लीटर पर आ गया।

कच्चे तेल की कीमत में तेजी

बुधवार को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.44 डॉलर की तेजी के साथ 99.75 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। इसी तरह यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट भी 0.59 डॉलर की तेजी के साथ 92.23 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में काफी उठापटक देखी जा रही है। ईरान और पश्चिमी देशों के न्यूक्लियर डील के करीब पहुंचने की खबरों से इसमें गिरावट आई थी। लेकिन फिर सऊदी अरब की एक धमकी से इसमें तेजी आई। सऊदी अरब ने कहा था कि ओपेक प्लस देश कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। अब महंगाई के कारण मांग प्रभावित होने से इसमें गिरावट आ रही है।

अमेरिका की इच्छा, रूसी तेल की मूल्य सीमा तय करने वाले गठजोड़ में शामिल हो भारत

नयी दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका ने शुक्रवार को भारत से कहा कि वह रूसी तेल की मूल्य सीमा तय करने वाले गठजोड़ में शामिल हो। इस गठजोड़ का मकसद मास्को के लिए आय के साधनों को बाधित करना और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नरम बनाना है। भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए अमेरिका के उप वित्त मंत्री वैली अडेयेमो ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस की कमाई को सीमित करने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। कच्चे तेल की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने पर अमेरिका तथा अन्य जी-7 देश रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

अडेयेमो ने कहा कि रूस के ऊर्जा और खाद्यान्न व्यापार को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है और भारत जैसे देश स्थानीय मुद्रा सहित किसी भी मुद्रा का उपयोग करके सौदे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से आने वाले तेल के दाम की सीमा तय करने के प्रस्ताव में 'गहरी दिलचस्पी' दिखाई है। उन्होंने कहा कि मूल्य सीमा तय होने से रूस को मिलने वाले राजस्व में कमी आएगी। गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमले की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगाई हैं। अडेयेमो ने कहा, "दामों की सीमा तय करने को लेकर एकसाथ आने के बारे में भारतीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मेरी बात हुई है और उन्होंने इस विषय में गहरी दिलचस्पी भी दिखाई है। यह उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कीमतों को कम करने के भारत के उद्देश्य के अनुरूप है। हम उन्हें इस बारे में सूचनाएं दे रहे हैं और इस विषय पर संवाद जारी रहेगा।" दरअसल भारत समेत कुछ देशों ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है और इसी को देखते हुए अमेरिका, रूस से आने वाले तेल के दामों की सीमा तय करना चाहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडेयेमो से शुक्रवार को मुलाकात की और हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा तथा भारत की जी-20 की अध्यक्षता समेत विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ बातचीत की।

सीमाशुल्क विभाग आयातित वस्तुओं के लिए पांच सितंबर से एक समान जांच प्रणाली शुरू करेगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सीमा शुल्क विभाग आयातित वस्तुओं को मंजूरी देने के लिए देश में मानकीकृत जोखिम आधारित ऐसी प्रणाली शुरू करेगा जिसमें आमना-सामना हुए बिना मूल्यांकन (फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली) किया जाता है। इसकी चरणबद्ध शुरुआत पांच सितंबर से धातु की आयातित वस्तुओं के साथ की जाएगी। इससे सीमा शुल्क जांच में एकरूपता आएगी, माल की खेप को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम होगा और कारोबारी सुगमता बढ़ेगी।

अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिकारियों के लिए जारी परिपत्र में कहा है कि नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर (एनसीटीसी) ने विभिन्न मानकों के आधार पर बिल ऑफ एंट्री (बीओई) के लिए प्रणाली जनित केंद्रीकृत जांच आदेश विकसित किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। जोखिम आधारित यह जांच बीओई के लिए दूसरी जांच होगी। इसमें माल को भौतिक जांच के लिए भेजा जाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि सीमा शुल्क अधिकारी आयातित सामान का आकलन अधिकारियों के समक्ष जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर करेंगे। बीओई को आयातक या उनके एजेंट आयातित सामान के आने से पहले सीमा शुल्क विभाग में जमा करते हैं। सीबीआईसी ने कहा, "यह निर्णय हुआ है कि मानकीकृत सीमा शुल्क जांच प्रक्रिया की शुरुआत धातु की वस्तुओं के निरीक्षण के साथ पांच सितंबर 2022 से शुरू की जाएगी।" इसमें कहा गया कि इससे जांच में एकरूपता आने, इसमें लगने वाला समय और लागत कम होने का अनुमान है।

कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनियों का मार्जिन पहली तिमाही में 2.13 प्रतिशत घटा, राजस्व बढ़ा

मुंबई। एजेंसी

कच्चे माल की ऊंची लागत के कारण घरेलू कंपनियों के कारोबार में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 39 प्रतिशत का उछाल जरूर आया लेकिन उनका परिचालन मार्जिन 2.13 प्रतिशत घटकर 17.7 प्रतिशत पर आ गया। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर 620 सूचीबद्ध कंपनियों के विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा है कि कंपनियों ने जिंस और ऊर्जा के रूप में कच्चे माल की ऊंची लागत का बोझ ग्राहकों पर डाला। इससे राजस्व में वृद्धि तो हुई, लेकिन मार्जिन पर असर पड़ा है। मार्जिन में कमी का कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति व्यवस्था का बाधित होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। इक्रा ने कहा कि 620 कंपनियों के राजस्व में जून तिमाही में सकल रूप से 39.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका एक कारण पिछले साल कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण तुलनात्मक आधार का कमजोर होना है। दूसरा कारण विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में तेज वृद्धि है। हालांकि, पिछली तिमाही जनवरी-मार्च की तुलना में कारोबार में केवल 1.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। यह रुख विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। एजेंसी में उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख किंजल शाह ने कहा, "महामारी की दूसरी लहर के बाद मांग में सुधार के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में अधिकतर वस्तुओं, विशेष रूप से धातुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इससे मार्जिन पर दबाव बढ़ा है।" पहली तिमाही में कीमतों पर दबाव को लेकर चुनौती बनी रही और इससे मार्जिन प्रभावित हुआ। इससे, इस तिमाही में परिचालन लाभ मार्जिन 2.13 प्रतिशत घटकर 17.7 प्रतिशत रह गया।

प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए क्षेत्र, स्थान आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने की जरुरत : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत को अपनी प्रमुख औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियों को फिर से तैयार करने के लिए क्षेत्र और स्थान या गंतव्य आधारित वृद्धि से जुड़ी पहल पर ध्यान देने की जरूरत है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि मजबूत रही है और यह तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कमजोर सामाजिक प्रगति, बढ़ती असमानता से पता चलता है कि यह वृद्धि कई भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार पर खरा उतरने में विफल रही है। 'भारत100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रूपरेखा' शीर्षक की रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) और इंस्टिट्यूट फॉर कम्पेटिटिविनिस (आईएफसी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। इसे ईएसी-पीएम के चेयरमैन डॉ. बिबेक देबरॉय ने जारी किया। यह रिपोर्ट ईएसी-पीएम और आईएफसी के बीच एक सहयोगी प्रयास है। इसे संस्थान के चेयरमैन अमित कपूर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर और क्रिश्चियन केटेल्स ने तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, "भारत को अपनी कुछ प्रमुख औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियों को फिर से तैयार करने के लिए क्षेत्र और गंतव्य आधारित वृद्धि की पहल की जरूरत है।" रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि क्षेत्र और गंतव्य आधारित पहल से व्यक्तिगत समूहों और क्षेत्रों की विशेष जरूरतों की पहचान की जा सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को ऐसी सामाजिक नीतियों को सक्षम करने की आवश्यकता है जो श्रम बाजार में काम करने वालों की रोजगारोन्मुखता को बढ़ाएं और नौकरी चाहने वालों के लिए बाधाओं को कम करें। रिपोर्ट में पाया गया कि नियामकीय ढांचा इस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त है तथा 'विरासत में मिला बाजार ढांचा भारत की वृद्धि को पीछे खींच रहा है। इसलिए भारत को प्रतिस्पर्धा से जुड़ी कंपनियों की वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

अवादा ग्रुप ने 40,000 करोड़ रुपए के ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत के '2070 नेट-जीरो' लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के अग्रणी इंटीग्रेटेड एनर्जी एंटरप्राइज अवादा ग्रुप ने हाल ही में राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन राजस्थान में कोटा में ग्रीन अमोनिया फेसिलिटी और अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने के संबंध में है।

नई दिल्ली में आयोजित इनवेस्टमेंट राजस्थान शिखर सम्मेलन के लिए निवेश प्रोत्साहन रणनीति के हिस्से के रूप में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इस कदम से लगभग 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर और 10,500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार हासिल होगा।

इस समझौते को देश के ग्रीन फ्यूचर के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए अवादा ग्रुप के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल ने कहा, "हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और इस तरह नेट-जीरो से संबंधित लक्ष्यों की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। अवादा में हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए हरित ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत को ऊर्जा के लिहाज से स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अवादा में, हम मानते हैं कि व्यापार और सस्टेनेबिलिटी साथ-साथ चलती है। हम इस साझेदारी के लिए राजस्थान सरकार के आभारी हैं। यह माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की हरित ऊर्जा क्रांति को मजबूत करने में मदद करेगा, क्योंकि हम अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में देश की शानदार तरक्की को सपोर्ट करने के लिए नवीन स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं।"

स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित टैक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मित्तल ने आगे बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जलते के दौरान भी स्वच्छ रहती है और सिर्फ जल वाष्प को पीछे छोड़ती है। उन्होंने आगे कहा, "उन उद्योगों के लिए जिन्हें उच्च तापमान वाली हीट की आवश्यकता होती है, जैसे कि फाउंड्री और ग्लास और स्टील निर्माता, यह अभूतपूर्व हो सकता है क्योंकि यह न केवल जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय स्रोतों से बदल देगा, बल्कि ग्रीन अमोनिया और गैस के विकल्प का भी उत्पादन करेगा।"

चीन की कंपनियों के 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं : चंद्रशेखर

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चीन की मोबाइल कंपनियों को भारत से अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों के 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि देश के इलेक्ट्रॉनिक पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय कंपनियों की भी भूमिका है लेकिन इसका मतलब विदेशी ब्रांडों को बाहर करना नहीं है।

उन्होंने कहा, "केवल एक मुद्दा है, जो हमने उठाया है। इसे चीन के कुछ ब्रांड के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से रखा गया है। हमने कहा है कि हमारी अपेक्षा यह है कि वे अधिक निर्यात करें।" चंद्रशेखर ने कहा, "आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से कलपुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और अधिक खुला होना चाहिए। बाजार के एक विशेष खंड (12,000 रुपये से कम) से चीन की कंपनियों को बाहर निकालने के बारे में हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे नहीं पता है कि यह मामला या विषय कहां से आया।" उन्होंने चीन की कंपनियों को 12,000 रुपये से कम के मोबाइल फोन बेचने से रोकने के लिए सरकार की एक कथित योजना पर सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उद्योग निकाय आईसीईए के सहयोग से इक्रियर द्वारा तैयार एक रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के साथ 120 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुंचना चाहती है।

पंजाब सरकार कपास पर 'आढ़तियों' का कमीशन घटाकर एक प्रतिशत करेगी

चंडीगढ़। एजेंसी

पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को कहा कि किसानों के लाभ के लिए कपास पर 'आढ़तियों' का कमीशन 2.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। धालीवाल ने कहा कि धान और गेहूं की तुलना में अनाज मंडियों में कपास के मामले में ऐसा कोई खर्च नहीं है। धान और गेहूं की फसलों पर सफाई, भरने, तौलने और परिवहन पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि सरकार कपास किसानों के हित में पहले ही कपास पर बाजार शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर चुकी है। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, धालीवाल ने मंगलवार को पंजाब कॉटन फैक्ट्रीज एंड गिनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में कपास के कई कारखाने बंद होने के कगार पर हैं या कुछ नुकसान के कारण बंद भी हो गए हैं। उन्होंने मंत्री से राज्य में कपास की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाने का भी आग्रह किया।

शेयर बाजार में सतर्कता रखने की जरुरत

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 में जुलाई 2022 से अब तक करीब 15 फीसदी की तेजी के बाद विश्लेषक अब इक्विटी बाजारों पर सतर्क रुख अपना रहे हैं। विश्लेषकों ने अल्पावधि में गिरावट का अनुमान जताया है। उनके मुताबिक क्रेडिट सुइस वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय इक्विटी में तेज सुधार से उसका मूल्यांकन सर्वाधिक ऊंचे स्तरों पर पहुंच गया है। एमएससीआई इंडिया सूचकांक प्रदर्शन के लिहाज से एमएससीआई वर्ल्ड और एमएससीआई ईएम के मुकाबले 37 फीसदी और 96 फीसदी ऊंचे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। भारत का 12 महीने का पीई बढ़कर 19.5 गुना पर पहुंच गया है और यह मौजूदा समय में 10 ईयर मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन (एसटीडी) ऊपर कारोबार कर रहा है। जैसे ही अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में तेजी आनी शुरू हुई है, और मंदी का जोखिम गहराया है, भारतीय इक्विटी बाजारों में कुछ गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कहा है कि यदि बड़ी गिरावट आती है तो यह भारत के मजबूत बुनियादी आधार और प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर विकास संभावनाओं को देखते हुए दीर्घावधि निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर साबित हो सकती है।उन्होंने लिखा है, 'हम पोर्टफोलियो के संदर्भ में मिडकैप कंपनियों में अपने 'ओवरवेट' नजरिये पर कायम हैं। अल्पावधि में हम बैंकों और फार्मा के साथ साथ उन क्षेत्रों को पसंद कर रहे हैं जिन्हें त्योहारी सीजन से पहले ऊंचे उपभोक्ता खर्च का लाभ मिल सकता है।'

कम बोवनी से मूंगफली की कीमतों में तेजी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मूंगफली की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह मूंगफली की बोवनी कम होना है। बोवनी में कमी की वजह कपास के दाम ज्यादा मिलने से किसानों द्वारा मूंगफली की बजाय कपास की खेती को ज्यादा तरजीह देना है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार इस माह मंडियों में मूंगफली के दाम 4 से 5 फीसदी बढ़ चुके हैं। हालांकि अब आगे कीमतों में ज्यादा तेजी के आसार नहीं है। नई फसल आने पर मूंगफली के दाम घट सकते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 44. 32 लाख हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की बोआई हो चुकी है जो पिछली समान अवधि में 47. 95 लाख हेक्टेयर में हुई बोवनी से करीब साढ़े 7 फीसदी कम है। सबसे बड़े मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात में बोवनी करीब 10 फीसदी घटकर 17 लाख हेक्टेयर में हुई। तीसरे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में बोवनी करीब 15 फीसदी घटी है। हालांकि दूसरे प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान में मूंगफली की बोवनी करीब 2 फीसदी ज्यादा हुई। गौरतलब है कि गुजरात के सौराष्ट्र में मूंगफली और कपास दोनों की खेती खूब होती है। किसानों को इस बार कपास के दाम अच्छे मिले तो इस साल मूंगफली की बजाय कपास की खेती पर ज्यादा जोर दिया। बता दें कि अगस्त माह में ज्यादातर तिलहन की कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन बोवनी घटने के कारण मूंगफली के दाम बढ़े हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल से मूंगफली की बोवनी करीब साढ़े 7 फीसदी कम हुई है। जिससे इसके दाम बढ़ रहे हैं। अगस्त माह में अब तक मूंगफली के दाम करीब साढ़े 4 फीसदी बढ़ चुके हैं। इस माह आवक भी कम हो रही है। जानकारों के मुताबिक जुलाई में मंडियों में करीब 2. 11 लाख टन मूंगफली कीआवक हुई थी जबकि अगस्त में अब तक 1. 33 लाख टन आवक हो चुकी है। इस समय मंडियों में मूंगफली के भाव 7000 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। नई फसल अक्टूबर में आएगी। तब तक मूंगफली की कीमतों में गिरावट के आसार नहीं है।

बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने पर भी निकाल सकते हैं 10 हजार रुपये, सरकार की इस योजना के पूरे हुए 8 साल

नई दिल्ली। एजेंसी

ये बात साल 2010 की होगी। यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले कमलेश बचत करने के लिए बैंक में खाता खुलवाना चाहता था। वह कई बैंकों में गया लेकिन उसका बचत खाता नहीं खुल पाया। बैंकों में खाता खुलवाने के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त थी। वहीं कहीं कागजों की कमी तो कहीं रुपये कम पड़ने की वजह से कमलेश का खाता नहीं खुल पाया। कमलेश ने कई बैंकों में दर-दर की ठोकरें खाई लेकिन किसी भी बैंक में खाता नहीं खुल पाया। इसमें सबसे बड़ी समस्या आई गारंटर की। किसी बैंक में कमलेश को खाता खुलवाने के लिए गारंटर नहीं मिला। ये दिक्कत सिर्फ कमलेश नहीं उसके जैसे बहुत से गरीब लोगों के साथ आई। किसी का भी बैंक में खाता नहीं खुल पाया। बैंक में खाता नहीं खुल पाने का असर उनकी बचत पर पड़ता था। वहीं कई अन्य लाभ भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाते थे।

केंद्र सरकार ने साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए सरकार देश के नागरिकों को तक बैंक की सुविधाएं पहुंचाना चाहती थी। इस खाते को कस्टमर्स जीरो बैलेंस पर खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने पर आपको कई तरह की सुविधा मिलती है। इस योजना (PM Jan Dhan Yojana) से कमलेश जैसे लाखों लोगों को बैंक में खाता खुलवाने की सुविधा मिली। आज इस योजना (PMJDY) को आठ साल पूरे हो गए हैं। आपको बताते हैं कि योजना में अभी तक कितने लोगों ने खाते खुलवाए और उन्हें क्या-क्या लाभ मिले। वहीं इस योजना में किस तरह खाता खुलवाया जा सकता है।

बहुत काम की योजना

ये योजना गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस योजना में सबसे बड़ी सुविधा ओवरड्राफ्ट की मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कोई भी खाताधारक कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपके बैंक मैनेजर से बात करनी होगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक तरह का लोन ही है। अगर बैंक आपको परमिशन देता है तो आप आसानी से यह विड्रॉल कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर आपको रोजाना के हिसाब से ब्याज चुकाने होंगे। पहले पीएम जनधन खाता में 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता था। अब इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा पाने के लिए आपका जनधन खाता कम से कम 6 महीना पुराना होनी चाहिए। अगर आपकी खाता 6 महीने पुरानी नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपको केवल 2 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी।

इस तरह खुलवा सकते हैं खाता

सरकार की इस योजना के तहत आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक पासपोर्ट साइज के फोटो की जरूरत होती है। इसमें 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने वालों को रूपे डेबिट कार्ड मिलता है। वहीं एटीएम कार्ड पर 2 लाख रुपयों का बीमा कवर भी मिलता है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की भी सुविधा मिलती है।

अब तक इतने लोगों ने खुलवाए हैं खाते

सरकार की इस योजना में अभी तक 46.25 करोड़ लाभार्थियों के खाते खुले हैं। वहीं खोले गए बैंक खातों में 1.73.954 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। योजना के तहत मार्च साल 2015 में खातों की संख्या जहां 14.72 करोड़ थी। वहीं ये 10 अगस्त साल 2022 तक तीन गुना बढ़कर 46.25 करोड़ तक पहुंच गई।

महिलाओं के भी खुले खाते

योजना के तहत महिलाओं के भी खूब खाते खोले गए हैं। इसमें 56 फीसदी जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं। इसमें 67 फीसदी जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 31.94 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं।

सरकार 'भारत' ब्रांड के तहत बेचेगी सभी सब्सिडी वाले उर्वरक, छपा आएगा PMBJP का लोगो

नई दिल्ली। एजेंसी

यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले सभी उर्वरक अब आपको बाजार में 'भारत' ब्रैंड नेम के साथ मिलेंगे। इन उर्वरकों की बिक्री सरकार अक्टूबर से 'भारत' नाम के एकल ब्रांड के तहत करेगी। उर्वरकों को समय पर किसानों को उपलब्ध कराने और मालढुलाई सब्सिडी की लागत घटाने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (PMBJP) के तहत 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' पहल की शुरुआत भी की। मांडविया ने कहा कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को 'भारत' ब्रांड के तहत ही बेचा जा सकेगा।

बोरी पर लगेगा पीएमबीजेपी का लोगो

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियां बोरी के एक-तिहाई हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य जरूरी सूचनाएं दे सकेंगी। लेकिन उर्वरक की बोरी के दो-तिहाई हिस्से पर भारत ब्रांड (Bharat) और पीएमबीजेपी का लोगो लगाना होगा। भले ही यह व्यवस्था अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन उर्वरक कंपनियों को अपना मौजूदा स्टॉक बेचने के लिए दिसंबर के अंत तक का समय दिया गया है।

बीते साल सरकार ने दी 1.62 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 1.62 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी दी थी। पिछले पांच महीनों में उर्वरकों के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये हो जाने की आशंका जताई गई है।

यूरिया की कीमत में होती है 80 फीसदी सब्सिडी

मांडविया ने भारत ब्रांड के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री किए जाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, "सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य के 80 फीसदी की सब्सिडी देती है। इसी तरह डीएपी की कीमत का 65 फीसदी, एनपीके की कीमत का 55 फीसदी और पोटाश की कीमत का 31 फीसदी सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा उर्वरकों की ढुलाई पर भी सालाना 6,000-9,000 करोड़ रुपये लग जाते हैं।"

अभी अलग-अलग नाम से बिकता है उर्वरक

उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनियां अलग-अलग नाम से ये उर्वरक बेचती हैं, लेकिन इन्हें एक से दूसरे राज्य में भेजने पर न सिर्फ ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराने में भी समस्या आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी।

3एफ ऑयल पाम अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत तेल पाम कारखाना स्थापित करेगी

मुंबई। एजेंसी

हैदराबाद स्थित 3एफ ऑयल पाम ने मंगलवार को कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश में एक एकीकृत तेल पाम कारखाना स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 3एफ ऑयल पाम ने बयान में कहा, "कंपनी ने फरवरी में परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश में 120 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण से संबंधित सभी आवश्यक अनुमोदन और वैधानिक मंजूरी भी प्राप्त हो गई है।" कारखाने को दो चरणों में विकसित किया जाना है। पहला चरण सितंबर, 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। इससे 300 से अधिक लोगों के लिए स्थानीय रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस एकीकृत पामतेल परियोजना में एक पामतेल प्रसंस्करण और परिशोधन, एक शून्य निर्वहन अपशिष्ट संयंत्र, पाम कचरा आधारित बिजली संयंत्र और समर्थन कार्यों के लिए अन्य भवन और गोदाम शामिल होंगे। कंपनी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 3एफ ऑयल पाम के पास लगभग 2,000 हेक्टेयर का ऑयल पॉम रकबा है। 3एफ ऑयल पाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक संजय गोयनका ने कहा, "हम 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत तेल पाम कारखाने को लेकर खुश और उत्साहित हैं।"

राजमार्ग मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन के अनुरूप देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है। इस समय जारी किए जा रहे आईडीपी के प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। इस कारण, कई नागरिकों को विदेश में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में आईडीपी के मुद्दे के लेकर नागरिकों की सुविधा के लिए 26 अगस्त, 2022 को एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया, "अब, इस संशोधन के जरिए आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में एक जैसा रूप देने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप मानकीकृत किया गया है।" अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सेंट-गोबेन इंडिया ने इंदौर में अपना एक्सक्लूसिव 'माय होम' स्टोर लॉन्च किया इंदौर में पहला एक्सक्लूसिव स्टोर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सेंट-गोबेन लाइट और निर्माण के स्थायी समाधान बनाने में दुनिया की प्रमुख कंपनी है जिसका फोकस अपने उद्देश्य 'दुनिया को रहने के लिए बेहतर घर' बनाने पर केंद्रित है। भारत में 1.35 अरब लोग रहते हैं और यहां शहरीकरण की मौजूदा दर 32 फीसदी है। आने वाले सालों में हमें लाखों घरों की जरूरत होगी। महामारी ने घरों को हमारे अस्तित्व का केंद्र बना दिया है, क्योंकि हम घरों से काम कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। घरों के लिए तरह-तरह के समाधानों की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सेंट-गोबेन ने कई नए-नए सॉल्यूशंस विकसित किए हैं। इसमें शावर क्यूबिकल्स, खिड़कियां, किचन के शटर्स, वार्डरोब शटर्स, एलईडी शीशे, ग्लास राइटिंग बोर्ड, जिप्रोक सीलिंग्स, ड्राईवॉल, टाइलिंग और ग्राउटिंग सॉल्यूशंस, जिप्सम प्लास्टर, सर्टेन टीड रूफिंग शिंगल्स और नोवेलियो वॉल कवरिंग समेत अन्य कई सॉल्यूशंस शामिल हैं। सेंट-गोबेन इन सभी सॉल्यूशंस को माय होम के तहत लेकर आया है, जो कि एक संपूर्ण फिजिटल बिजनेस मॉडल है। माय होम अपने उपभोक्ताओं को डिजाइनिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक के समाधानों की पेशकश करता है।

बेहतर आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, रहन-सहन पर कम खर्च और रियल एस्टेट के आकर्षक दामों ने टियर 2 और टियर 3 शहरों को घरों के खरीदारों और निवेशकों के लिये रियल एस्टेट का सुगम ठिकाना बना दिया है। यह शहर तेजी से रियल एस्टेट बाजारों के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हाउसिंग सेगमेंट मजबूत है, जो बुनियादी ढांचे की समग्र वृद्धि का पूरक है। इंदौर ऐसा ही एक शहर है, जो रियल एस्टेट के हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। दूसरे लॉकडाउन के बाद से इस शहर ने आवासीय संपत्तियों की मांग में बेहद तेज बढ़ोतरी देखी है। सेंट-गोबेन इंडिया ने इंदौर शहर में अपना मायहोम स्टोर खोला है, जो कि मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, ताकि इस क्षेत्र में होम सॉल्यूशंस की बढ़ रही मांग पूरी हो सके।

गणेश चतुर्थी 31 अगस्त, विशेष

विघ्नविनाशक-प्रथम पूज्य गणपति बप्पा मोरया...

पुराणों के मुताबिक गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्तिभाव और उत्साह-उमंग से मनाया जाता है। यही वजह है कि इन दिनों देश भर में गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जगह-जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। इस पर्व की भव्यता और इससे जुड़ी मान्यताओं पर एक दृष्टि।

धार्मिक पर्व

आर. सी. शर्मा

हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेशजी की वंदना के बिना शुरू नहीं होता, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश विघ्नविनाशक हैं। कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी शुभ कार्य में बाधा आए, इसलिए हर शुभ कार्य के पहले गणपति की स्थापना और उनकी पूजा होती है। लेकिन देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान उन्हें उनकी बुद्धि-विवेक से प्राप्त हुआ है।

पौराणिक मान्यता

एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद हुआ कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा होनी चाहिए। तब सभी देवतागण स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारदजी ने इस स्थिति के समाधान के लिए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने इस समस्या को सुलझाने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में सभी देवगणों को अपने-अपने वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड का सात चक्कर लगाने थे, जो देवता सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करके वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा, वही प्रतियोगिता का विजेता होगा और सर्वप्रथम पूज्यनीय माना जाएगा। तब सभी देवगण अपने-अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेशजी भी इसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। लेकिन गणेशजी का वाहन तो चूहा था, जिसकी गति धीमी थी। तब गणेशजी ने बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की जगह अपने माता-पिता यानी शिव-पार्वती की सात परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे, तब भगवान शिव ने गणेशजी को इस प्रतियोगिता का विजयी घोषित किया। शिव ने कहा, 'गणेश, तुमसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुके हैं।' कार्तिकेय द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, 'माता-पिता की परिक्रमा करके उन्होंने साबित कर दिया कि माता-पिता का दर्जा ब्रह्मांड से बढ़कर है।' गणेश ने अपने इस आचरण से पृथ्वीवासियों को संदेश दिया कि धरती में माता-पिता ही हमारे सर्वस्व होते हैं, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है।

बुद्धि-बल के अधिष्ठाता

गणेशजी न सिर्फ विघ्नविनाशक और बुद्धि के देवता हैं, वे सबसे बड़े धर्मज्ञ भी हैं। धर्म के दस लक्षण होते हैं और इन सभी लक्षणों में बुद्धि का महत्व सबसे ऊपर है। धर्मशास्त्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिसके पास बुद्धि है, वही बलशाली है। अतः गणेशजी न सिर्फ बुद्धि बल्कि बल के भी अधिष्ठाता हैं।

प्रतिमा स्थापना-विसर्जन

गणेश पुराण के मुताबिक गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही हुआ था। इसीलिए यूं तो पूरे साल में हर दिन गणेशजी की पूजा भक्तगण करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी (जो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को आती है) का दिन और इसके बाद के दस दिन पूरी तरह से गणेशजी को समर्पित होते हैं। इस 11 दिन के पर्व में पहले दिन यानी चतुर्थी को गणेशजी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पश्चिम भारत में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में इस दिन लोग अपने घरों, सोसायटीज में या सामूहिक रूप से मुहल्लों में बनाए गए पंडालों में गणेशजी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। स्थापना के पहले उनकी प्रतिमा को गाजे बाजे और 'गणपति बप्पा मोरया' के उद्घोष के साथ स्थापना स्थल तक लाया जाता है। मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके बाद अगले 11 दिनों तक पूरा माहौल गणेशमय रहता है। कुछ लोग दो दिन, कुछ लोग तीन दिन, कुछ लोग एक ही दिन अलग-अलग लोग अपनी अपनी श्रद्धा और सुविधा के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित की गई प्रतिमा को अपने घर, सोसायटी या मुहल्ले के पंडाल में रखते हैं। फिर उनकी प्रतिमा का विर्सजन कर दिया जाता है।

होती है विशेष पूजा-अर्चना

गणेश चतुर्थी में की गई गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद जितने दिनों तक इन्हें अपने घर में रखते हैं, उनकी नियमित रूप से पूजा होती है। जिन पंडालों में 11 दिन तक गणेशजी विराजते हैं, वहां शाम की आरती के बाद भक्तगण झूमते-नाचते हैं, भजन गाते हैं और गणेशजी की भक्ति में लीन रहते हैं। k

तिलक ने की थी गणेशोत्सव की शुरुआत

गणेश चतुर्थी धार्मिक पर्व होने के साथ उसका सामाजिक और कुछ मायने में राजनीतिक महत्व भी है। आज जिस तरह के सार्वजनिक गणेश पूजाओं का चलन है, इसकी बकायदा सोच-समझकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के सेनानी बालगंगाधर तिलक ने सन् 1893 में शुरुआत की थी। तब इसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक एकजुटता भी थी। स्वाधीनता सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। इस तरह भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इस पर्व की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। k

एमजी मोटर इंडिया ने पेश की एडवांस ग्लॉस्टर

एमजी मोटर इंडिया ने आज 31.99 लाख रुपये से शुरू होने वाली एडवांस्ड ग्लॉस्टर के लॉन्च की घोषणा की है भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी अब नए और एडवांस सेफ्टी स्टाइल और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स के साथ आई है मौजूदा ग्लॉस्टर के एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम में अतिरिक्त फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स हैं जैसे कि डोर ओपन वार्निंग रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और लेन चेंज असिस्ट 30 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अतिरिक्त यह फीचर एडवांस ग्लॉस्टर को सुरक्षित और आसान ड्राइव बनाते हैं।

लॉन्च पर एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव चाबा ने कहा टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव निरंतर विकास और बेस्ट-इन-क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस एमजी में हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं ग्लॉस्टर की पहचान बोल्ड, मजबूत, वर्सेटाइल और शानदार होने की है और हम फीडबैक के लिए अपने कस्टमर के आभारी हैं अपने 2डब्ल्यूडी और 4डब्ल्यूडी ट्रिम्स पावरफुल इंजन ऑप्शन, अगली पीढ़ी की तकनीक, ऑटोनॉमस लेवल 1 और माय एमजी शील्ड पैकेज के साथ एडवांस्ड ग्लॉस्टर को हमारे नए जमाने के कस्टमर्स को खुश और उत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि हम प्रोडक्शन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए लोकलाइजेशन बढ़ा रहे हैं सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर रहे हैं हम इस लॉन्च के साथ ग्लॉस्टर की बिक्री को दोगुना करने की उम्मीद कर रहे हैं। एडवांस ग्लॉस्टर की सड़क पर मौजूदगी को 4डब्ल्यूडी वैरिएंट्स में पूरी तरह से नए ब्रिटिश विंडमिल टर्बाइन-थीम वाले अलॉय मेटल व्हील्स ने और मजबूत बना दिया है। इसे अब नए डीप गोल्डन कलर ऑप्शन में पेश किया जा रहा है जो एसयूवी की अपील को और शानदार बनाता है मेटल ब्लैक, मेटल ऐश और वार्म व्हाइट के पहले से मौजूद रंगों के अलावा नया रंग जोड़ा गया है।

एडवांस्ड ग्लॉस्टर आपको राइड के दौरान भी मनोरंजन प्रदान करता है अपने सेगमेंट में बेस्ट 31.2सेमी टचस्क्रीन और 12 स्पीकरों के हाई-क्वालिटी ऑडियो सिस्टम के साथ आती है इसमें एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले के साथ-साथ फर्स्ट-इन-सेगमेंट शॉर्टपीडिया न्यूज ऐप और गाना भी शामिल है आप बोलकर कमांड दे सकते हैं और यह फीचर आपको गाना पर आपके मनचाहे गानों को खोजने में मदद करेगा एसयूवी ने 75 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स के अपने एडवांस और स्मार्ट-टेक को मिलाकर अपनी पेशकश और समृद्ध बनाया है। 6 और 7 सीटर विकल्पों के साथ 2डब्ल्यूडी और 4डब्ल्यूडी में उपलब्ध एडवांस्ड ग्लॉस्टर अपने साथ बेजोड़ प्रीमियम लग्जरी और बेस्ट-इन-क्लास इंटीरियर स्पेस लाती है एडवांस्ड ग्लॉस्टर पावरफुल 2.0लीटर डीजल इंजन के साथ आत है जो दो विकल्पों में उपलब्ध है बेस्ट-इन-सेगमेंट 158.5 किलोवॉट पावर प्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट-इन-सेगमेंट ट्विन-टर्बो डीजल इंजन शामिल है।

एमजी ग्लॉस्टर की पहचान कंफर्ट और लग्जरी के लिए है यह विरासत आपको एडवांस्ड ग्लॉस्टर में भी मिलती रहेगी यह बेस्ट-इन-क्लास फीचर्स सड़क पर विशाल मौजूदगी पावरफुल कैपेबिलिटी और शानदार इंटीरियर के साथ आती

है एसयूवी में इंटेलिजेंट 4डब्ल्यूडी 7मोड के साथ ऑल-टेरेन सिस्टम एक ड्यूल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12-वे पावर एडजस्ट ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट मसाज और वेंटिलेशन फीचर, और वायरलेस चार्जिंग, इसके कई उल्लेखनीय फीचर्स में शामिल है। एडवांस्ड ग्लॉस्टर 180 से अधिक आफ्टर-सेल्स सर्विस विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कार ऑनरशिप प्रोग्राम माय एमजी शील्ड भी पेश करेगा ग्राहकों को स्टैंडर्ड 3ऊ3ऊ3 पैकेज की पेशकश की जाएगी, यानी तीन साल की असीमित किलोमीटर की वारंटी, तीन साल रोड साइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री पीरियॉडिक सर्विसेस।

पाकिस्तान के व्यापार मंडल का भारत से सब्जियों के आयात की अनुमति देने का आग्रह

इस्लामाबाद। एजेंसी

पाकिस्तान के एक प्रमुख व्यापार मंडल ने मंगलवार को सरकार से आग्रह किया कि विनाशकारी बाढ़ के कारण देश में सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए वाघा सीमा के रास्ते भारत से सब्जियों का आयात फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एलसीसीआई) का अनुरोध पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के यह कहने के एक दिन बाद आया है कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ व्यापार संबंधों को कम करने के तीन साल बाद भारी बाढ़ के कारण खड़ी फसलों के नष्ट होने के बाद भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर सकती है। 'द न्यूज इंटरनेशनल' अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थिति यह है कि टमाटर के दाम 500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं और प्याज 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे आम लोगों के लिए भारी संकट पैदा हो गया है।

एलसीसीआई ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत से सब्जियां आयात करने की अनुमति दे। रिपोर्ट में एलसीसीआई के अध्यक्ष नौमान कबीर के हवाले से कहा गया है, ''हाल ही में आई बाढ़ ने देशभर में टमाटर, प्याज, आलू और अन्य सब्जियों की फसलों को नष्ट कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों तक संकट के बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सब्जियों का संकट और गहरा सकता है। उन्होंने सरकार से तेजी से निर्णय लेने का आग्रह किया क्योंकि वाघा सीमा के रास्ते भारत से पाकिस्तान तक सब्जियां पहुंचाने में कुछ दिन लगेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने अगस्त, 2019 में भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को सीमित कर दिया था।

ऑडी को भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में और तेजी की उम्मीद, फिर उतारा क्यू3 मॉडल

नयी दिल्ली। एजेंसी

जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी ऑडी वैश्विक आपूर्ति चिंताओं के बावजूद इस साल भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में दो अंकीय वृद्धि बरकरार रखने में सफल रही है। कंपनी को भरोसा है कि आगामी त्योहारी मौसम में उसकी बिक्री में और तेजी आएगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने मंगलवार को कहा कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर काफी आशान्वित है। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग में तेजी का सिलसिला त्योहारी मौसम में और जोर पकड़ने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑडी ने मंगलवार को अपने लोकप्रिय मॉडल क्यू3 को नए सिरे से पेश किया। दो साल के अंतराल के बाद क्यू3 अब फिर से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी शोरूम कीमत 44.89 लाख रुपये रखी गई है।

बीपीसीएल की 2040 तक 10 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजना

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की दूसरी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की वर्ष 2040 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाकर 10 गीगावॉट तक ले जाने की योजना है। बीपीसीएल के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को शेयरधारकों की सालाना बैठक में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हमने 2040 तक खुद को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाली कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीपीसीएल अपने कारोबार का विस्तार एवं विविधीकरण कर रही है जिससे न केवल अतिरिक्त राजस्व स्रोत पैदा होंगे बल्कि तेल एवं गैस कारोबार में किसी भी तरह की गिरावट आने पर एक तरह की गारंटी भी मिलेगी। सिंह ने कहा, ''कंपनी ने छह रणनीतिक क्षेत्रों- पेट्रोरसायन, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता खुदरा बिक्री, ई-मोबिलिटी और अपस्ट्रीम की पहचान भावी विकास के स्तंभ के तौर पर की है। यह 2040 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के मद्देनजर किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि बीपीसीएल फिलहाल 50 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा ही पैदा करती है लेकिन 2025 तक इसे एक गीगावॉट और 2040 तक बढ़ाकर 10 गीगावॉट करने की योजना है।

यूनियन एएमसी ने यूनियन रिटायरमेंट फंड को लॉन्च करने की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

यूनियन एएमसी ने आज यूनियन रिटायरमेंट फंड के लॉन्च की घोषणा की। यह असीमित अवधि के लिए रिटायरमेंट समाधान उपलब्ध कराने वाली योजना है, जिसमें लॉक-इन पीरियड 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक (इनमें से जो भी पहले हो) होता है। यूनियन रिटायरमेंट फंड ('योजना') का न्यू फंड ऑफर (NFO) का शुभारंभ 1 सितंबर, 2022 को होगा, और इसका समापन 15 सितंबर, 2022 को होगा। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के गुणकों में निवेश किया जा सकता है।

यूनियन रिटायरमेंट फंड ऐसे समय में आया है जब विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को रिकॉर्ड एट्रिशन द्वारा चुनौती दी जा रही है। कर्मचारी उद्योगों में बदलाव का विकल्प चुन रहे हैं और कुछ तो पूर्णता, अर्थ और उद्देश्य की तलाश में अस्थायी नौकरियों के पक्ष में पूरी तरह से बाहर भी हो रहे हैं। इस ट्रेंड के मुकाबले जीवन प्रत्याशा में वृद्धि (स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत में जीवन प्रत्याशा । 30 साल से बढ़कर लगभग 70 साल हो गई है) हो गई है, तथा रिटायरमेंट के बाद के वर्षों की आज़ादी का सही मायने में लाभ उठाने के लिए गंभीरता से योजना बनाने और अनुशासन की जरूरत है। ग्राहकों को आवश्यक अनुशासन प्राप्त करने में मदद करने के लिए इस योजना की संरचना को डिजाइन किया गया है। इस योजना में लॉक-इन पीरियड 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो, होता है और केवल एक इक्विटी निवेश योजना की पेशकश करता है।

इस योजना के बारे में बताते हुए, श्री जी. प्रदीपकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), यूनियन एएमसी, ने कहा, 'यूनियन रिटायरमेंट फंड सिर्फ NFO नहीं है। यह एक ऐसा बिगुल है जो वित्तीय योजना के साथ महत्वाकांक्षी योजना के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। नवीनीकरण योजना दर्शाती है कि अनुशासित तरीके से आजादी का आनंद लेने के लिए किस तरह सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है। यह सिर्फ पैसे जमा करने की कोशिश करने या धन जमा करने की योजना से कहीं बढ़कर है।'

रिलायंस की 5जी सेवाएं दिवाली तक शुरू होंगी, दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी

मुंबई। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि समूह की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो 5जी नेटवर्क के विकास पर दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इस साल दिवाली तक देश के कुछ बड़े शहरों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।

अंबानी ने आरआईएल की 45वीं सालाना आमसभा (एजीएम) की बैठक में यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जियो अगले साल के अंत तक पूरे देश में 5जी सेवाएं देने लगेगी। अंबानी ने कहा, ''समूचे देश में सही मायने में 5जी नेटवर्क खड़ा करने के लिए हम कुल दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जियो ने भारत जैसे बड़े आकार वाले देश के लिए 5जी सेवा शुरू करने के लिए सबसे तेज और सबसे महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। दो महीनों के भीतर, दिवाली तक हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जियो 5जी की शुरुआत कर देंगे।'' उन्होंने कहा कि भारत में 5जी सेवाएं महानगरों में शुरू होने के बाद जियो हर महीने अपनी मौजूदगी बढ़ाती जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2023 आने तक देश के हर कस्बे एवं तहसील तक जियो की 5जी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। रिलायंस ने हाल में संपन्न नीलामी में 88,078 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदा है। उसी समय कंपनी ने कहा था कि वह देश में उन्नत 5जी नेटवर्क खड़ा करेगी।

अंबानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि जियो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेटा-प्रवर्तित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत 'ट्रू 5जी' से कम का हकदार नहीं है और 5जी सेवा सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जियो 5जी सेवाएं देने के लिए पांचवीं पीढ़ी के नवीनतम संस्करण को तैनात करेगा जिसमें 4जी नेटवर्क पर निर्भरता शून्य हो जाती है। इसके साथ ही जियो नई एवं शक्तिशाली सेवाओं की आपूर्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि जियो दुनिया के सभी अग्रणी वैश्विक स्मार्टफोन उपकरण विनिर्माताओं के करीबी संपर्क में काम कर रही है।

अंबानी ने कहा कि जियो ने देशभर में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क खड़ा कर लिया है और आज फाइबर-टु-द-होम (एफटीटीएच) का हर तीन में से दो नया उपभोक्ता जियो को ही चुन रहा है। उन्होंने कहा कि जियो 5जी दूरसंचार के क्षेत्र में पासा पलटने वाला साबित होगा। अंबानी ने कहा, ''भारत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अपनाने के मामले में दुनिया में अभी 138वें स्थान पर है। जियो भारत को इस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों तक ले जाएगी।''

दुकानदारों को भी मिलेगी पेंशन!

नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में ईपीएफओ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी है। स्वरोजगार में लगे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) ने अपनी रिटायरमेंट स्कीम्स में शामिल होने के लिए सैलरी और कर्मचारियों की संख्या की सीमा हटाने का प्रस्ताव दिया है। इससे फॉर्मल सेक्टर के सभी कर्मचारी और स्वरोजगार में लगे लोग रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स के दायरे में आ सकते हैं। ईपीएफओ अभी स्टेकहोल्डर्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। साथ ही उसने इस बारे में राज्यों से भी संपर्क साधा है। फिलहाल, इसके लिए अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होती है।

साथ ही वही कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं जिनके कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे अधिक है। ईपीएफ स्कीम के 5.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

15,000 रुपये सैलरी और 20 कर्मचारियों की लिमिट के प्रावधान को खत्म करने के लिए इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रॉविजन एक्ट, 1952 में बदलाव करना होगा। इस बदलाव के बाद स्वरोजगार वाले भी ईपीएफओ स्कीम से जुड़ सकेंगे। इस बदलाव के बाद अपने काम में लगे लोग भी ईपीएफओ से जुड़ सकेंगे। एक सीनियर अधिकारी ने ईटी से कहा कि फॉर्मल सेक्टर से सभी कर्मचारियों और स्वरोजगार में लगे लोगों को इस स्कीम में जोड़ने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। इनमें कर्मचारियों की संख्या और सैलरी की सीमा हटाना शामिल है। इससे फॉर्मल सेक्टर के सारे कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, फिर चाहे उनकी सैलरी और कंपनी में कर्मचारियों की संख्या जो भी हो।

अभी ईपीएफ के लिए अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होती है। ईपीएफओ अपने मेंबर को प्रॉविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस की सुविधा देता है। ये सुविधाएं ईपीएफ, इम्पलॉयी पेंशन स्कीम और इम्पलॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के जरिए दी जाती है। सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने से ईपीएफओ का कॉर्पस भी बढ़ेगा। अभी यह 12 लाख करोड़ रुपये का है। अभी ईपीएफओ अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का 15 फीसदी ईटीएफ में निवेश करता है। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी तक ले जाने की योजना है।

भारत में डाटा केंद्र उद्योग का आकार 5.6 अरब डॉलर, आगे भी विस्तारः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत के डाटा केंद्र उद्योग का आकार करीब 5.6 अरब डॉलर मूल्य का है और वर्ष 2025 तक देशभर में 45 से अधिक नए केंद्र खोले जाएंगे। एनारॉक और बिनस्वेंगर की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में इस समय 138 डाटा केंद्र कार्य कर रहे हैं जो करीब 1.1 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में फैले हैं। इनकी 37 मेगावॉट की मौजूदा आईटी क्षमता का 57 प्रतिशत सिर्फ मुंबई और चेन्नई शहरों में ही है। 'भारत में डाटा केंद्र विस्फोट पर एक नजर' शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि अगले तीन साल में 1.3 करोड़ वर्ग फुट आकार और 1,105 मेगावॉट आईटी क्षमता वाले 45 डाटा केंद्र देश में और खुलने वाले हैं। महामारी के जोखिम के बीच मांग में बढ़ोतरी से इसे समर्थन मिल रहा है। नए डाटा केंद्रों में स्थापित होने वाली कुल आईटी क्षमता का करीब 69 प्रतिशत मुंबई और चेन्नई में ही नजर आएगा। इस तरह 2025 के अंत तक भारत में कुल 183 डाटा केंद्र काम करने लगेंगे जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल करीब 2.4 करोड़ वर्ग फुट और आईटी क्षमता 1,752 मेगावॉट की होगी। दोनों सलाहकार फर्मों का मानना है कि भारत एक डाटा केंद्र क्रांति के करीब पहुंच चुका है। एक समय छोटा एवं बिखरा हुआ उद्योग रहा यह क्षेत्र बड़ी तेजी से एक विशाल एवं समेकित उद्योग की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। एनारॉक कैपिटल के अध्यक्ष (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक और डाटा सेंटर) देवी शंकर ने कहा, ''भारतीय डाटा केंद्र उद्योग का मौजूदा आकार करीब 5.6 अरब डॉलर का है और इसका तेजी से बढ़ना तय है। महामारी की वजह से पैदा हुए हालात ने इस कारोबार को गति दी है।'' बिनस्वेंगर के प्रबंध साझेदार जेफ बिनस्वेंगर का मानना है कि दुनिया खासकर एशिया-प्रशांत एवं भारत में डाटा केंद्र इस समय तमाम निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का आधार-स्तंभ बने हुए हैं।

बेयर ने लॉन्च की केरेन्डिया, डायबिटीज़ पीड़ित मरीज़ों में क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ की रफ्तार धीमी करने वाली इनोवेटिव मेडिसिन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बेयर ने भारत में केरेन्डियाऊश ब्रैंड के तहत् फिनरेनॉन को लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनरेनॉन अपनी तरह की पहली नॉन-स्टेरॉयडल, सलेक्टिव मिनिरलोकॉर्टिकॉयड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो क्रोनिक किडनी रोगों तथा टाइम 2 डायबिटीज़ मरीज़ों को दी जाती है। हाल में कराए गए इंडियन क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ (सीकेडी) अध्ययन से यह सामने आया है कि मधुमेह भारत में क्रोनिक किडनी रोगों तथा एंड-स्टेज किडनी डिज़ीज़ के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।1 मधुमेह से ग्रस्त 40% से अधिक रोगी आगे चलकर क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ के भी शिकार बनते हैं। 2.भारत में 7.4 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं और 2030 तक इस आंकड़े में बढ़ोतरी होकर 9.3 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, और यह महामारी का रूप ले लेगी।3.देश में मधुमेह ग्रस्त लोगों की संख्या के हिसाब से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।

श्री मनोज सक्सेना, प्रबंध निदेशक, बेयर ज़ायडस फार्मा ने कहा, ''क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ और डायबिटीज़ रोगियों में थेरेपी का मुख्य ज़ोर एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ या किडनी फेलियर से बचाव करने पर रहता है। थेरेपी के बावजूद, इन मरीज़ों की हालत लगातार बिगड़ते हुए किडनी फेल होने की नौबत आ जाती है।4 फिनेरेनॉन इन मरीज़ों के लिए उपचार की पेशकश करता है जिससे क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का बढ़ना भी कम होता है और किडनी फेल होने का जोखिम भी घटता है। साथ ही, यह क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ से जुड़े हृदय रोग संबंधी जोखिमों को भी कम करता है।5इसके अलावा,जिन मरीज़ों की किडनी फेल हो चुकी होती है और इलाज के लिए डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट पर निर्भर होते हैं, उन मरीज़ों तथा उनके परिवारों के लिए यह भारी आर्थिक बोझ होता है।''

CKD से ग्रस्त T2D मरीज़ों में, फिनरेनॉन काफी अलग होती है। यह मिनिरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर (एमआर) ओवरएक्टीवेशन को अवरुद्ध करती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक्ड्के गंभीर होने तथा कार्डियोवास्थ्युलर क्षति पहुंचाने में योगदान करती है।

फिनरेनॉन के फेज़ III क्लीनिकल परीक्षण प्रोग्राम में दुनियाभर में 13000 मरीज़ों को शामिल किया गया ताकि टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित क्रोनिक किडनी डिजीज़ रोगियों में किडनी एवं कार्डियोवास्क्युलर संबंधी सुरक्षा एवं प्रभावों की जांच-पड़ताल की जा सके। इन नतीजों से यह सामने आया है कि फिनरेनॉन, ऑप्टीमाइज़्ड रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकेड (RAS)के अलावा, =57% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (eGFR) किडनी कंपोजिट आउटकम के जोखिम को 23% कम करता है, तथा कंपोजिट सीवी आउटकम में 14% तक कमी आती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।